Mission.

मध्य प्रदेश के बीना शहर में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

1681. **श्री राघवजी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में बीना शहर के पास तेल शोधक कारखाने की स्थापना के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या यह सच है कि इसके निर्माण में विलम्ब हो रहा है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इसका निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) और (ख) सरकार ने 1686 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा घटक सहित 5277 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से मध्य प्रदेश में बीना में 6 एम एम टी पी ए क्षमता वाली ग्रासरूट ईंधन/लाब्स रिफाइनरी की स्थापना तथा वाडीनार में सिंगल पाइंट भूरिंग और कच्चे तेल के टर्मिनल सहित संबंधित क्रूड आयात सुविधा एवं क्रास कंट्री पाइपलाइन के लिए मै० भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव का 11.12.95 को अनुमोदन कर दिया है। परियोजना के सरकारी अनुमोदन की तिथि से 42 महीनों के भीतर यांत्रिक रूप से पूर्ण होने तथा यांत्रिक पूर्णता के बाद छः महीनों के भीतर चालू होने का अनुमान है। चूंकि परियोजना हाल ही में अनुमोदित की गई है इसलिए इसके निर्माण में कोई विलंब नहीं है।

Discussion with the U.S. Official on Regional Arm-Race

1682. SHRI PASUMPON THA KIRUTTINAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have discussed the matter in regard to resumption of American aid to Pakistan leading arms race in the sub continent with the U.S. Assistant Secretary during her visit in November, 1995; and

(b) if so, the details of the discussions and the outcome thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes, Sir.

(b) The clear and firm position of Government of India against the proposal to supply sophisticated military equipment to Pakistan through the mechanism of the Brown Amendment, and the strong adverse reaction that this had caused in Indian political and public opinion was reiterated to the US Assistant Secretary.

The US assessment, which we do not accept, is that the transfer of the $368 million military package to Pakistan would not alter the military balance in the region. The US Government has also stated that they have no intention of trying to dismantle the Pressler Amendment as a whole, or of extending the one-time waiver to bring in the F-16 aircraft later.

Supply of Gas to Gas based Plants in Tripura

1683. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 512 given in the Rajya Sabha on 15th March, 1995 and state:

(a) the short term and long term plans to utilise proven gas reserves in Tripura;

(b) whether KRIBHCO had lost interest because of non allocation of 1.3 MMSCMD of gas as recommended by MOF on 31st August, 1992;

(c) whether logistic constraints are more insurmountable than bringing gas from Oman; and

(d) whether ONGC/GAIL have taken any special steps for allocation of gas for industries in backward states like Tripura and special consideration is given to the gas users, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND

NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) At present 0.29 MMSCMD is being utilised in Tripura. The utilisation is expected to go up with the commissioning of power plant of NEEPCO, at Ramchandranagar. 1.64 MMSCMD has been allocated for utilisation by power plants and industrial units in Tripura.

(b) No tangible progress has been made in the implementation of the project proposed by KRIBHCO because of non-availability of ground water, unsuitable terrain, difficulties in transportation of equipment and the non-availability of the quantity of gas required by KRIBHCO.

(c) There are no insurmountable constraints in developing the gas reserves of Tripura.

(d) In order to encourage the utilisation of gas in the North-East the Government have fixed a concessional price of Rs. 1000/MCM with a further discount of Rs.400/MCM on a case to case basis.

Developmet of New Ports in Maharashtra and Gujarat

1684. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Maharashtra and Gujarat Governments have submitted proposals to develop four new ports in the States;

(b if so, what are the details thereof, indicating cost and capacity of the ports; and

(c) how far it is likely to ease the pressure of the port of Bombay?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. RAJASEKARA MURTHY): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

जल परिवहन के लिए नदियों का उपयोग किया जाना

1685. **श्री सोमपाल:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की मुख्य नदियों की बड़े पैमाने पर जल पविहन के लिए प्रयुक्त करने के संबंध में कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को लागू करने से पूर्व इन नदियों के पहले से ही प्रदूषित जल के और अधिक प्रदूषित हो जाने के प्रभाव के पक्ष पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० राजसेकर मूर्ति): (क) और (ख) जी हां।

देश में अन्तर्देशीय जलपरिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित तीन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया है और इन राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए प्रयास किए हैं:

(1) हल्दिया से इलाहाबाद तक (1620 कि० मी०) गंगा-भागीरिथी-हुगली नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग-1 घोषित किया गया है।

(2) बंगलादेश सीमा और सदिया के बीच (891 कि० मी०) ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग-2 घोषित किया गया है।

(3) टोल्लाम से कोट्टापुरम (168 कि०मी०) तक पश्चिमी तटीय नहर और उद्योग मंड़ल नहर (23 कि०मी०) तथा चम्पाकारा नहर (14 कि० मी०) को राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के रूप में घोषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कुछ और जलमार्गों को भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है, जैसे सुन्दरबन, गोदावरी और गोवा जलमार्ग। पूर्वीतटीय नहर, काकीनाडा-मद्रास नहर इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य जलमार्गों पर अध्ययन किया जा रहा है और तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के बाद इन पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी हां।

अन्तर्देशीय जल परिवहन, पर्यावरण की दृष्टि से